



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 238] नई दिल्ली, बुधवार, मई 31, 1995/ज्येष्ठ 10, 1917
No. 238] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 31, 1995/JYAISTHA 10, 1917

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 1995

सं. 25/95-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन टी)

सा.का.नि. 468(अ).—केन्द्रीय सरकार, उत्पादशुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 का (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) दत्त नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (संशोधन) नियम, 1995 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. उक्त नियम के नियम 57 में,—

(i) उपनियम (2) में, “मांग की सूचना के 10 दिन के भीतर” शब्दों और अंकों के स्थान पर “मांग

की सूचना की प्राप्ति की तारीख से 3 मास के भीतर” शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ii) इस प्रकार संशोधित उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम (3) जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“(3) जहां विनिर्माता या निर्धारिती, उपनियम (1) के अधीन या उपनियम (2) के अधीन अवधारित रकम का मांग की सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर, संदाय करने में असफल रहता है, वहां वह, इस प्रकार अवधारित रकम के अनिवारित तीन मास की उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पश्चात् की तारीख से संदाय की तारीख तक ऐसी दर में व्याज का, जो शीर्ट द्वारा अधिनियम की धारा 11क के अधीन निपट किया जाए, संदाय करेगा।

3. उक्त नियम के नियम 57 में,—

(क) विद्यमान नियम को उपनियम (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा;

(ख) परन्तुक में, “उचित अधिकारी को” शब्दों के पश्चात् “3 मास के भीतर” शब्द और अंक जोड़े जाएंगे;

(ग) उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम (2) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(2) जहाँ, कोई विनिर्माता या निर्धारित उपनियम (1) के निबंधनों के अनुसार अनुज्ञापन रकम का, ऐसे अनुज्ञापन किए जाने की सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर, संदाय करने में असफल रहता है, वहाँ वह, इस प्रकार अनुज्ञापन रकम के अतिरिक्त तीन मास की उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पश्चात् की तारीख से संदाय की तारीख तक ऐसी दर से व्याज का, जो बोर्ड द्वारा अधिनियम की धारा 11क के अधीन नियत किया जाए, संदाय करेगा।”

4. उक्त नियम के नियम 574 में,—

(क) उपनियम (3) में “मांग की सूचना के 10 दिन के भीतर” शब्दों और अंकों के स्थान पर “मांग की सूचना की प्राप्ति के तीन मास के भीतर” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम (4) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

(4) जहाँ, विनिर्माता या निर्धारित उपनियम (1) के अधीन या उपनियम (2) के अधीन अवधारित रकम का मांग की सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर, संदाय करने में असफल रहता है, वहाँ वह, इस प्रकार अवधारित रकम के अतिरिक्त, तीन मास की उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पश्चात् की तारीख से संदाय की तारीख तक ऐसी दर से व्याज का, जो बोर्ड द्वारा अधिनियम की धारा 11क के अधीन नियत किया जाये, संदाय करेगा।

5. उक्त नियम के नियम 173 फ में,—

(क) उप-नियम (2) में, “प्राप्ति होने के दस दिन के भीतर” शब्दों के स्थान पर “प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जाएंगे, अर्थात्:—

“परन्तु जहाँ निर्धारित, कमी का निर्धारण आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर संदाय करने में असफल रहता है, वहाँ वह कमी

के अतिरिक्त तीन मास की उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पश्चात् की तारीख से ऐसी कमी की संदाय की तारीख तक ऐसी दर से व्याज का, जो बोर्ड द्वारा अधिनियम की धारा 11क के अधीन नियत किया जाए, संदाय करेगा।

परन्तु यह आर का उक्त अधिक प्राप्ति मध्य शुल्क निर्धारित के जमा खाने में नियम 173 के उपनियम (3) के अधीन विवरणी फाइल करने की तारीख से तीन मास के भीतर देने का आदेश नहीं किया जाता है, वहाँ उक्त निर्धारित दो तीन मास की उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पश्चात् की तारीख से संदाय की तारीख तक, ऐसी दर से व्याज, जो बोर्ड द्वारा अधिनियम की धारा 11क के अधीन नियत किया जाए, संदाय किया जाएगा।”

[फा सं 268/29/95-के.उ.शु.-8]

आई.पी. लाज, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 1995

NO. 25/95-CENTRAL EXCISES (NON-TARIFF)

G.S.R. 468(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Excise (Amendment) Rules, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the said rules, in Rule 57-1 of the Central Excise Rules, 1944 (hereinafter referred to as the said Rules):

(i) in sub-rule (2), for the words “within ten days of the notice of demand”, the words “within three months from the date of receipt of the notice of demand” shall be substituted.

(ii) after sub-rule (2) as so amended, the following sub-rule (3) shall be added, namely:—

“(3) where a manufacturer or an assessee fails to pay the amount determined under sub-rule (1) or under sub-rule (2) within three months from the date of receipt of demand notice, he shall pay, in addition to the amount so determined, interest at such rate as may be fixed by the Board under

section 11 AA of the Act, from the date immediately after the expiry of the said period of three months till the date of payment”.

3. In Rule 57 P of the said rules,

- (a) the existing rule shall be numbered as sub-rule (1);
- (b) in the proviso, after the words “proper officer”, the words “within 3 months” shall be added;
- (c) after sub-rule (1), the following sub-rule (2) shall be inserted, namely :—

“(2) where a manufacturer or an assessee fails to pay the amount disallowed in terms of sub-rule (1) within three months from the date of receipt of communication of such disallowance, he shall pay, in addition to the amount so disallowed, interest at such rate as may be fixed by the Board under section 11 AA of the Act, from the date immediately after the expiry of the said period of three months till the date of payment”.

4. In Rule 57 U of the said rules,

- (a) in sub-rule (3), for the words “within ten days of the demand”, the words “within three months of the receipt of the notice of demand” shall be substituted.
- (b) after sub-rule (3), the following sub-rule (4) shall be inserted, namely :—

“(4) where a manufacturer or an assessee fails to pay the amount determined under sub-rule (2) or under sub-rule (3) within three months from the date of receipt of notice of demand, he shall pay, in addition

to the amount so determined, interest at such rate as may be fixed by the Board under section 11 AA of the Act, from the date immediately after the expiry of the said period of three months till the date of payment”.

5. In Rule 173-I of the said rules,

- (a) in sub-rule (2), for the words “within ten days of receipt”, the words “within three months from the date of receipt” shall be substituted;
- (b) after sub-rule (2), the following provisions shall be added, namely :—

“Provided that where an assessee fails to pay the deficiency within three months from the date of receipt of assessment order, he shall pay, in addition to the deficiency, interest at such rate as may be fixed by the Board under section 11 AA of the Act, on such deficiency from the date immediately after the expiry of the said period of three months till the date of payment of such deficiency.

Provided further that where duty on account of excess receipt is not ordered to be taken in the credit of the assessee within three months from the date of filing of return under sub-rule (3) of rule 173 G, there shall be paid to that assessee, interest at such rate as may be fixed by the Board under section 11 BB of the Act, on such excess receipt from the date immediately after the expiry of said period of three months till the date of payment”.

[F. No. 268/29/95-CX-8]

I. P. LAL, Dy. Secy.